[Shri R. K. Birla]

15.25 HRS.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

The third point I would like to state is about co-ordination. It is very important that there should be full co-ordination between all the departments of the railways, particularly between the Marketing and Sales Organisation which has been recently set up and the activities of the operating department. All efforts of the new organisation to secure more traffic can be easily undone if the operating department fails to provide sufficient wagons or to move the loaded traffic in time.

One of the most important points is about the accumulation of wagons and severe restrictions at some points. Whenever there is some accumulation of wagons at certain points, the operating department unhesitatingly rushes to put severe restrictions on bookings and supply of wagons. Such restrictions go on not only for days, but for weeks and weeks together, with the result that the indentors do not get the wagons in time and suffer heavily in the meantime. The operating department and the marketing and sales organisation have therefore got to work hand in hand to retain whatever traffic the railways have already got and to secure additional traffic. In some cases it may be necessary for the railways to quote specially reduced rates to attract more traffic and more revenue.

Now I come to the transhipment points at various places which is also a very important point. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the desired improvement of transhipment capacity at some points is very necessary. The railway users on the Western Railway in particular, and also on the Northern Railway, have almost continuous difficulty in getting their goods moved *via* Viramgam, Sabarmati, Delhi-Sarai Rohilla and Hissar. The capacity of the railways to tranship from metre guage to broad guage and *vice versa* is totally insufficient, and I am sure that the hon. Minister has not forgotten the very serious crisis which has just taken place a short while ago in the region of Saurashtra. The thermal power stations which are considered public utility concerns were on the verge of closure on account of shortage of coal. Coal was lying at Viramgam Station, but could not be transhipped on the metre guage wagons because, it was said, there was a shortage of wagons. This shortage was, however, removed in time by the railway authorities to tranship more coal wagons, but in this process the capacity left for other goods was severely cut, and this resulted in restrictions on movement of other goods *via* this point. It is high time that the authorities took some bold steps to remove these two bottlenecks at the transhipment points I have just now stated.

The most important point which I would like to state is about economy in fuel consumption. It is a very major item of expenditure, and it should be possible to effect substantial economy on this account. Table XVII at pages 56-57 of the blue book shows that on the metre guage more fuel was consumed per thousand gross ton kilometer on both passenger and goods trains, and on the broad guage also more coal was consumed on the passenger side.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may continue on the next occasion.

15.30 HRS.

DISCUSSION RE : STATEMENT ON AGITATION BY DELHI SCHOOL TEACHERS

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up the dicussion under rule 193. We have just one hour. How much would the Minister require?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN): About twenty minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, we have forty minutes at our disposal. I have received slips from several Mem-

bers and I shall try to accommodate as many as possible.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : 20 मिनट मिनिस्टर साहब ले लेंगे, आधा घंटा प्रस्तावक ले लेंगे तो फिर हम लोग क्या लेंगे ?

श्री रवि राय (पुरी) : पहले से बता दीजिए कि कितना टाइम हमको मिलेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have to call Mr. Gupta. He will be very brief. I should also like to request the hon. Minister to be brief and finish within 15 minutes.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): It is an important discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall give you time.... (*Interruptions.*) We have forty minutes and about twelve people want to speak. So, two or three minutes each. Let us start now. Mr. Gupta will take five minutes.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Sir, you are making history. No mover of any motion has ever taken only five minutes. I need more time.

उपाध्यक्ष जी, माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने 20 फरवरी के भापण में दिल्ली के टीचर्स की स्ट्राइक के सम्बन्ध में जो तस्वीर खींची है वह ऊपर से बड़ी लुभावनी लगती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह गलत तो है ही, साथ ही साथ बड़ी मिसलीडिंग भी है। उन्होंने यह कहा है कि अपने भाषण में कि दिल्ली के टीचर्स को पहले भी एक स्केल मिल चुका है सन् 1959 में उन्होंने कहा है कि दिल्ली के टीचर्स को मदरास, बम्बई और हिन्दुस्तान की सब स्टेट्स से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। उन्होंने आखिर में यह भी कहा कि और सरकार के पास और अधिक पैसा हो तो और भी बढ़ा दे लेकिन पैसे की बड़ी दिक्कत है, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया है वह बहुत किया है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं सदन को और दिल्ली के लोगों को कि उन्होंने अभी तक 15 लाख रुपया ज्यादा बढ़ाया है जिसका मतलब यह है कि यहां पर 30 हजार अध्यापक हैं। और एक अध्यापक को एक महीने में केवल 4 रुपया ज्यादा मिलेगा। यह है जो कि उन्होंने अध्यापकों को दिया है, उनके इतनी मेहनत करने के बाद और लगातार दो साल एजीटेशन चलाने के बाद। उपाध्यक्ष जी, यह जो कुछ उन्होंने दिया है उसका फायदा 30 हजार लोगों में से केवल एक हजार लोगों को मिलेगा। यह है इनकी देन जिसकी तस्वीर उन्होंने इस सदन के सामने बड़े सुन्दर तरीके से खींची है।

उपाध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि 1959 के अन्दर एक पे-स्केल बढ़ाया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1959 में क्या हुआ। उस समय गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जितना भी डी॰ ए॰ था वह सभी बेसिक पे में जोड़ दिया गया और उसी की वजह से टीचर्स का भी जोड़ा गया। क्या यह पे रिवीजन का कोई तरीका है ? क्या यह पे स्केल्स का रिवीजन है ? मैं आप से पूछना चाहता हूं। आपने यूनिवर्सिटी टीचर्स के पे स्केल्स, आजादी मिलने के बाद आज तक, एक बार नहीं बल्कि दो बार रिवाइज किए हैं। पहले उनको 250 मिलते थे लेकिन आपने उनके 400 रु॰ कर दिए। लेकिन यहां पर आपने क्या किया है ? यहां पर जो एम॰ ए॰, बी॰ टी॰ है, उसको ढाई सौ या पौने तीन सौ मिलेगा जबकि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट यह कहती है कि यूनिवर्सिटी टीचर्स में और स्कूल टीचर्स में अगर क्वालिफिकेशन एक ही है तो कम से कम अन्तर होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी टीचर की पे का मिनिमम 4 सौ रु॰ है और वह 9 सौ रु॰ तक जाता है और यहां पर इन्होंने रिवाइज करने के बाद जो ग्रेड दिया है एम॰ ए॰, बी॰ टी॰ को वह 250 या 275 और ज्यादा से ज्यादा 550 तक। वहां का टीचर तो एम॰ ए॰ भी हो सकता है लेकिन यहां पर टीचर को एम॰ ए॰, बी॰ टी॰, होना चाहिए या दो

[श्री कंवर लाल गुप्त]

साल का एक्स्पीरियेन्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन्स अच्छी होने के बाद भी आप उनको ग्रेड नहीं देते। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आजादी के बाद आजतक 20 साल में इतनी महंगाई बढ़ने के बाद हमारे शिक्षा मन्त्री ने केवल एक बार 4 रुपया एक महीने में एक टीचर को दिया है।

कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है, उपाध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने कहा कि हमने उस कमीशन की रिपोर्ट से ज्यादा दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जो हिसाब लगाते हैं, उनका वह हिसाब अलग ही होता है। स्कूल और कालेज में जो हिसाब पढ़ाया जाता है उससे अलग हिसाब इस मन्त्रालय का होता है। ये कहते हैं कि जो बेसिक पे है उसके अन्दर, जितना भी डीयेरनेस और सिटी एलाउन्स है, सारे इमालुमेन्ट्स जोड़ देने चाहिएं और फिर उसके बाद वह मुकाबला करते हैं। मन्त्री महोदय ने मद्रास, कलकत्ता और बम्बई की बात भी कही। मैं कहता हूं कि आप बड़े-बड़े शहरों कि बात छोड़ दीजिए। मैं तो हरियाणा और पंजाब की बात करना चाहता हूं, मैं तो कोठारी कमीशन की बात करना चाहता हूं। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि मिनिमम नेशनल पे एक टीचर की कितनी होनी चाहिये। इसको उन्होंने बताया है। उसमें डीयरनेंस एलाउन्स का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया है। दिल्ली का मुकाबला आप मद्रास और कलकत्ता से नहीं कर सकते, बल्कि आपको हरियाणा और पंजाब से दिल्ली का मुकाबला करना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश से मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मुकाबले में दिल्ली के टीचर्स की तनख्वाह ज्यादा है, तो मैं आपको आफ़र देता हूं कि आप किसी भी हाई-कोर्ट के जज को आर्बीट्रेटर मान लीजिए। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के चेप्टर 3 के अन्दर सारे टीचर्स की पे के बारे में ज़िक्र है। वह सारे का सारा केस उसको रेफर कर दीजिए। इसके साथ-साथ लोकल कन्डीशन्ज़ क्या हैं, उनका क्या कार्य होना चाहिये, पहले क्या था और दूसरी जगह क्या है, इन सारी बातों को जज देख लेगा। मैं प्वाइन्टेडली इस बात को कहना चाहता हूं कि आप इस सारे केस को उसे रेफर कर दीजिए। अगर आप उसको आर्बीट्रेटर मानने के लिये तैयार न हों, तो मैं कहता हूं कि हमारे उपाध्यक्ष जी को ही आर्बीट्रेटर मान लीजिए और अगर इनको भी नहीं मानना चाहते, तो फिर पार्लियामेंन्ट के मैम्बरों की ही कमेटी बना दीजिए, जिसमें कि कांग्रेस के लोग भी हों और अपोजीशन के लोग भी हों। अगर इन तीनों बातों में से आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो इसका मतलब यह होगा कि आपका केस खोखला है और उसमें कोई वजन नहीं है। जो कुछ भी आप कहते हैं वह मिसलीडिंग है।

उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने एक बात यह कही है कि इसमें फाइनेन्शल इम्पलीकेशन्ज़ हैं लेकिन मैं कहता हूं कि कोई फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने इनसे कहा कि हम 25 लाख रुपया देने के लिये तैयार हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी न तो रुपया लेते हैं और न खुद देने के लिये तैयार हैं। मैं कहता हूं यह तो आपकी ज़िम्मेदारी है, दिल्ली प्रशासन की इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। पे-स्केल्ज़ कितने हों, कहां तक बढ़ाए जाएं, यह सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का बेबी है, इसे तो आपको ही पालना होगा। अगर आप स्वयं इनको नहीं पाल सकते, तो फिर दिल्ली एड-मिनिस्ट्रेशन ने जो कहा है, वह उनको दीजिए। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आपको कुछ सिफारिशें की हैं। उनके मुताबिक जो सारा फाइनेन्शल इम्पलीकेशन होता है, वह 38 लाख का होता है, जो कि रेकरिंग एक्सपेन्सेज हैं और 66 लाख नान-रेकरिंग एक्सपेन्सेज हैं। 38 लाख में से 11 लाख कारपोरेशन खर्च करेगा। और आपके हिस्से में केवल 27 लाख आयेगा।

27 लाख में से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 25 लाख देने के लिये तैयार है, इस लिये मैं कहना चाहता हूं । कि आप दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिश को क्यों नहीं मानते हैं . . .

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): Teachers have been suspended, and you will not allow us this forum to speak? Should they settle it on the streets?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please keep something for other Members, and conclude.

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष जी, अभी क्या हो रहा है कि 6000 टीचर्स या तो डिस्मिस कर दिये गये हैं या सस्पेंड कर दिये गये हैं और 250 टीचर्स जेल में हैं । लोगों को गुरुद्वारे और मंदिरों में से पकड़ा जाता है और पीटा जाता है । कोई भी सभ्य सरकार इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकती है । मैं इस सरकार को कन्डेम करना चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि आप ट्रेड यूनियनज़ की तरह से इन के साथ व्यवहार नहीं कर सकते । आप ताकत से इन को दबा सकते हैं क्योंकि आप की हुकूमत है, लेकिन इकानोमिकली फस्ट्रेटेड और निरुत्साहित टीचर्स से क्या आप वह अपेक्षा करेंगे कि वह उन बच्चों को जोकि कल देश के नेता होने वाले हैं, पैदा कर सकें ? ऐसा नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक, दो बात कह कर खत्म करना चाहता हूं । हिमाचल प्रदेश के अन्दर आप टीचर्स का ग्रेड रिवाइज़ करने जा रहे हैं । अब दिल्ली की तरह वह भी यूनियन टैरीटरी है । वहां पर आप उनको बढ़ी हुई तनख्वाह देना चाहते हैं । मेरी समझ में मुरारजी भाई वहां इसलिए यह बढ़ोतरी करना चाहते हैं क्योंकि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहां के चीफ़ मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम उनको बढ़ी हुई तनख्वाह देंगे इसलिए वहां तो मुरारजी भाई ग्रेड बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यहां पर बढ़ाने के लिए वह तैयार नहीं हैं । दिल्ली में यहां पर जनसंघ की हुकूमत है और अगर सरकार इस तरह का पोलिटिकल डिस्क्रिमनेशन करती है तो यह एक बड़ी भद्दी मिसाल होगी । कम से कम उन जैसे लायक मंत्री से इस बात की अपेक्षा नहीं होती कि वह ऐसी गलत बात करेंगे । मैं चाहूंगा कि उन के लिए मेरे मन में जो एक इज्जत की भावना है उसे ठेस न पहुंचे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आखिर में मैं यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि इस सरकार को रीज़न की भाषा समझनी चाहिए । श्री मुरारजी भाई से मैं इस अवसर पर अपील करना चाहता हूं कि वह इस रीज़न की भाषा को समझ लें लेकिन अगर वह महज़ वाएलैंस की ही भाषा को समझने के लिए तुले हुए हैं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात होगी । जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो लोगों को यही कहूंगा कि आप वाएलैंस आदि मत करिये । हम स्ट्राइक के खिलाफ हैं । स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए यह हम कहते हैं लेकिन जब उन्होंने पूछा कि यह न करें तो हम और क्या करें तो उस का मेरे पास कोई जवाब नहीं था । मजबूर होकर उनको स्ट्राइक पर जाना पड़ा है लेकिन अब भी समय है कि इस समस्या का समाधान कर लिया जाये । लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपोजीशन पार्टियां सब मिल कर इस को अपने हाथ में ले लेंगी । कांग्रेस के लोग भी इस में शामिल होंगे और फिर मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि वह स्कूल न जायें और साथ ही इस सदन् के सारे लोग मिल कर इस सरकार का मुकाबला करें और तब उस में कांग्रेस के लोग भी होंगे और हम लोग भी उन के साथ होंगे ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मोशन इस समय हाउस के सामने बहस के लिए पेश है वह बड़ा गौरतलब

[श्री रणधीर सिंह]

मामला है। अब मास्टर लोग चाहे वह दिल्ली में हों, हरियाणा में हों, पंजाब में हों, असम में हों अथवा बंगाल में हों वह हमारे देश की जान हैं, हमारे देश का दिमाग हैं। वह टीचर्स हमारे देश के नवयुवकों के कैरैक्टर को बनाने वाले हैं।

आम तौर पर देखने से मालम होगा कि मास्टरों की हालत तसल्लीबख्श नहीं है। दिल्ली में खासतौर पर खराब है वैसे देखा जाए तो आम तौर पर सारे देश में ही टीचर्स की हालत बड़ी हैबतनाक और तशवीसनाक है। यहां मैं एक चीज गवर्नमेंट से ज़रूर कहना चाहूंगा और वह यह कि या तो वह यह कमिशन आदि बैठाया न करे और अगर कमीशन वह बैठाती है तो फिर वह उस की सिफारिशों को पूरा भी किया करे। अब सरकार ने लाखों रुपया इस कमिशन के सिलसिले में लगा दिया। उस ने कोठारी कमिशन बैठाया और उस ने एक इतनी मोटी 1000 सफे की किताब लिख मारी। अब जब कमिशन अपनी सिफारिश कर चुका तो गवर्नमेंट उस कोठारी कमिशन से भागती है। मैं पूरे जोर से यह बात कहना चाहता हूं कि जब पब्लिक को आप प्रामिस देते हैं तो फिर इस तरह से पब्लिक को आप बिट्रे क्यों करते हैं?

मैं पूरे जोर से इस बात को कहूंगा कि महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए या अपने पहले के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन हुए हमारे मौजूदा प्रधान डा० जाकिर हुसैन हुए या यह हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुए, यह सारे बड़े आदमी पहले मास्टरों के हक़ की बड़ी बात करते थे लेकिन ज्योंही वह कुर्सी पर बैठे वह कुर्सी से चिमट गए और वह मास्टरों को भूल गए। मैं यह बड़ी खुली बात कहना चाहता हूं। या तो कोई बात यह कहें नहीं और कहें तो फिर वह उसे पूरी करें। वैसे मैं जानता हूं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ज्यादा इस देश में मास्टरों के हित की बात और कोई नहीं समझता। आज यह विरोधी दल वाले भाई जोकि इस तरह से उन के लिए चिल्ला रहे हैं यह सब ढपली बजाने वाले आदमी हैं। यह सब ऐक्सप्लाएटर्स के झुंड हैं जोकि किसी भी तरह अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं और आज अभाग्यवश यह मास्टर लोग इनके हत्थे चढ़ रहे हैं जैसे कि पुलिस वाले डा० लोहिया के हाथ में चले गये थे। यह मास्टर लोग आज इन जनसंघियों और कम्युनिस्टों के हाथ में चले गये हैं जोकि इन की आड़ लेकर अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करने की फिराक में हैं। मैं अपने उन जनसंघी भाइयों से जोकि यहां इस तरह से मास्टरों के लिए चिल्ला रहे हैं पूछना चाहता हूं कि यह जो दिल्ली में मास्टरों को सस्पेंड किया गया है यह किस ने किया है? यह उन्हीं के छोटे या बड़े भाइयों ने अर्थात् दिल्ली के जनसंघी ऐडमिनिस्ट्रेशन ने मास्टरों को सस्पेंड किया है .... (व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, ऑन ए प्वाएंट ऑफ आर्डर ....

श्री रणधीर सिंह : प्वाएंट ऑफ़ आर्डर क्या है? आप को मेरी बात को सुनना होगा। अभी से घबड़ा गये। कोई प्वाएंट औफ़ आर्डर नहीं है बल्कि प्वाएंट ऑफ डिसऑर्डर है. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जस्ट ए मिनिट। मुझे प्वाइंट ऑफ़ आर्डर सुन लेने दीजिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा कहना यह है कि जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दिल्ली प्रशासन ने 6000 टीचरों को सर्विस से डिसमिस किया तो यह सर्विसेज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं यह दिल्ली प्रशासन के अंडर नहीं हैं। माननीय सदस्य इस में पार्टी का सवाल नहीं लायें, पार्टी क्वैश्चन वह इसे न बनायें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. Countering argument is no point of order.

श्री रणधीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह विरोधी दल वाले थोथी शोहरत लेने वाले हैं। हम थोथी शोहरत के पीछे अलबत्ता नहीं हैं लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि हमें मास्टरों से या उनके काज़ से हमदर्दी नहीं है। यह फौजी जवान और मास्टर लोग इस देश के यह दो सपूत हैं। अब फौजी लोग तो इन के हाथ चढ़ते नहीं लेकिन जैसा मैंने कहा मास्टर लोग इन के हाथों में चढ़ गये। मैं मिनिस्टर साहब से पुरजोर अल्फाज में कहना चाहूंगा कि वह टीचर्स की जस्ट डिमांड्स को ऐक्सैपट करने की तरफ़ क़दम बढ़ायें क्योंकि आप आज नहीं तो कल उन की मांग को मानेंगे ही इसलिए क्यों न ग्रेस से इस काम को करें और यह जो विरोधी दल वाले इस सिचुएशन का इस्तेमाल अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं उसे भी रोक दें। मिनिस्टर साहब बरायेकरम वह बात न करें जैसे कि हमारे यहां मसल मशहूर है : "बकरी दूध तो देती है लेकिन मेंगनी कर देती है।"

मुझे यकीन है कि मिनिस्टर साहब उनकी जस्ट डिमांड को मानेंगे क्योंकि उनके ज़मीर में है कि मास्टर हक की बात कहते हैं लेकिन ऐसा वह किसी के दबाव से नहीं करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी का सोशलिज्म का नारा है और हम ने अपना ध्येय **टु सर्व दी वीक ऐंड रेज़ दी फौलेन** रक्खा है। जाहिर है कि हम गरीबों की मदद करेंगे। मास्टर लोगों का लौट देश में हर कोई जानता है कि मिजरेबुल है। टीचर्स जोकि सारे देश के कैरैक्टर को बनाते हैं उन को अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर नेशन का कैरैक्टर कैसे बनेगा? उन से आप बात करें। प्रैस्टिज का सवाल इसे आप मत बनाइये। उन्हें आप अपने पास बुला कर उनकी कठिनाइयां मालूम करें और उन की जायज़ बात आप मानें।

यह अकेले दिल्ली के टीचर्स का ही सवाल नहीं है। हरियाणे के टीचर्स का भी सवाल है। चौधरी शेर सिंह यहां बैठे हुए हैं उनके लिए वहां के लोगों के दिलों में इज्जत है और मैं चाहूंगा कि वह उस शानदार इनकिलाब की अहमियत को समझें। हरियाणा के मास्टरों ने एक शानदार इनकिलाब कर रक्खा है और यहां के मास्टरों का इनकिलाब अगर हरियाणा के उस इनकिलाब से मिल गया तो देश इस तूफान को रोक नहीं सकेगा। मैं पूरे जोर से यह कहना चाहता हूं कि तूफान से पहले जो एक चेतावनी प्रकट हो रही है उसको देखें और समय रहते स्थिति को बेकाबू न होने दें। अगर कहीं मास्टरों के आन्दोलन और हड़ताल आदि के साथ तालिबिल्म भी मिल गये तो फिर उस तूफान को कोई नहीं रोक सकेगा। आप इस को क्यों नहीं रोकते हैं? मैं पूरे जोर के साथ गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि इन ढपली बजाने वाले लोगों के हाथ में मास्टरों को मत दो तालिबिल्मों को मत दो। इन मास्टरों को जोकि देश का बेहतरीन दिमाग है उनको इस तरह से बहकने मत दो। मेरी पुरजोर अपील है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और इसके लिए उन से बातचीत की जाए और इस समस्या को सुलझाया जाए। मैं बड़ा मशकूर हूं कि मुझे बोलने का समय दिया।

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : Mr. Deputy-Speaker, the teachers are decidedly the most responsible section of our community. They are most sobre and also most non-violent and upon them lies the biggest responsibility of building up the fortunes of our future generation and creating in them a sense of discipline. How our future generations going to behave lies largely in the hands of our teachers. A section which is so much responsible, into the hands of which depends the creation of the future society of our country, it is unfortunate that this section has permitted itself to be reduced to the level of trade union activities of the lowest level. This is the most

[Shri D. N. Patodia]

unfortunote part of it. When we look at the behaviour of the teachers resorting to this type of strike, it is a shocking contrast to the responsibility they have towards the society. They have also chosen a time which is vulnerable, just two weeks or four weeks before the examinations, which has affected as many as 7,50,000 students in Delhi alone. And the most shocking part of it is that they have gone to the extent of inciting students from attending classes. Not only that, they have gone to the extent of inciting or preventing those teachers who wanted to attend the schools. This is a trend which must be resisted. Are we to set an example to the students of this country by the behaviour of the teachers like this, whatever be the merits or demerits of the demands of the teachers? In this context, I wish to state that even in the most civilised countries of the world, the teachers are dealt with on a different level. They are not permitted to indulge in trade union activities. At many places they are not even permitted by law to resort to strikes. America is an example for that.

AN HON. MEMBER: No.

SHRI D. N. PATODIA : Yes, I can prove it.

SHRI M. L. SONDHI : Why are the teachers, who are non-violent, slandered on the floor of the House?

SHRI D. N. PATODIA: I am quoting from a book of McGraw-Hill Series entitled *Principles of Secondary Education*, page 486. It says :

> "Teachers must teach citizenship, but they are often not permitted to take an active part in politics by campaigning for a political party or even to be outspoken in their beliefs."

Here I want to say that these teachers were utilized or mis-utilized by the Congress Party during the elections to canvass support on behalf of the ruling party. Regarding labour organisations, the same publication says :

> "Labour activity and attempts to joint labour unions in order to protect themselves are frowned upon for teachers."

This is an example which we have to set before us and before the future generation. But the matter does not end there.

What has the Central Government and the State Government done in this direction all these years? Is it not a fact that such an important section of the society also deserves to be treated with such importance? Is it not a fact that the teachers in our country are by far the most poorest? Is it not a fact that the very fact that the poor teachers have to agitate for the redress of their grievances is the creation of the ruling party? They have created a condition that nobody in the society can take anything from the government unless they agitate for it. Therefore, the Government is definitely responsible for the conditions they have created and they must give reasonable thinking to the problem and before imposing any restrictions on the teachers not to misbehave they must create conditions in which they will be no necessity for them to agitate. Secondly, so far as this particular dispute is concerned, it is not a very important point. Possibly, both the parties have made it a prestige issue. We are living in a society and we must be practicable. We must not make it a political issue. We must sit across the table, if necessary, and devise means by which the face-saving of both the parties is assured and settle the issue.

श्री शशि भूषण बाजपेयी (खारगोन): उपाध्यक्ष महोदय, भारत की महान जनशक्ति की चेतना शिक्षक आज राजधानी में दुखी है। 238 शिक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं 2156 की सेवायें टरमिनेट की गई है, 2789 शिक्षक सस्पेंड किये गये हैं और 6219 नये शिक्षक अप्वाइंट किये गये हैं। इन लोगों के बारे में कहा गया कि शिक्षकों का आन्दोलन उचित नहीं है। मैं आप से बतलाऊं कि कितना शांतिपूर्ण आन्दोलन शिक्षको ने दिल्ली में

किया है। 30 हजार शिक्षक संगठित हो कर शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे हैं। उन के बारे में आज गलत प्रचार किया जा रहा है कि शिक्षक जो हैं वह हिंसा पर उतर आये हैं। यह बिल्कुल गलत है।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि कोठारी कमिशन की जो सिफारिशें हैं उन को मानना चाहिये। वे अमल में नहीं लाई गई हैं। पिछली बार श्री मल्होत्रा ने खुद कहा है कि :

"95 लाख रुपये का जो बाकी खर्चा बैठता है, दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन की करीब 17 या साढ़े 16 लाख की लाइबिलटी बैठेगी। परन्तु यदि फाइनेन्स मिनिस्ट्री में यह बात रुकी हुई है तो बाकी स्टेट्स को अपने रिसोर्सेज से मीट किया जाए।"

एक जगह वह कहते हैं कि :

"जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज के ग्रेड्स का सम्बन्ध है उनकी बहुत सी श्रेणियों को ग्रेड्स दो तीन दफा रिवाइज किये गये, परन्तु हमारे अध्यापकों के 20 साल से अब तक रिवाइज नहीं किये गये जबकि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि इन के ग्रेड्स रिवाइज होने चाहिये।"

लेकिन हैरानी की बात है कि दिल्ली प्रशासन के एक नोट में कहा गया है कि :

"दिल्ली के अध्यापकों के लिए पिछले वर्षों में यह तीसरा परिशोधन है जब कि अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों के अभी तक दो ही वेतन परिशोधन हुए हैं।

2. दिल्ली के अध्यापकों के वेतनक्रम पहले ही शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतनक्रमों से अधिक थे, अब और भी अधिक हो गये हैं।"

यह दो बातें हैं (**व्यवधान**) फाइनेन्स मिनिस्टर के घर जन संघी ले गये उन्हें हड़ताल कराने के लिये। पहले हड़ताल करा दी और उसके बाद मझधार में छोड़ दिया शिक्षकों को। (**व्यवधान**) जन संघ के कौंसिलर वहां मौजूद थे।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षकों को जो हथकड़ी पहनाई गई है वह उन के साथ अन्याय हो रहा है। यह बहुत गलत है। किस ऐडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि उन को बर्खास्त किया जाये। उन की मांगे जायज हैं, उन की लड़ाई शांतिपूर्ण है। (**व्यवधान**) मैं कहना चाहता हूं कि उन को मझधार में छोड़ कर गलत जगह पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन उन की मांगें पूरी होंगी क्योंकि वह शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are some who were teachers and who are represented here. I would like to give everybody a chance but would restrict it to three minutes only for each. Professor Mukerjee.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : I shall speak telegraphically.

33,0000 teachers are on strike. They are supported by college and university teachers also. The Minister himself is a former teacher. He knows that teachers prefer quiet ways. They are not congenitaly perverse. They are carrying on a dignified movement. So many of them are languishing in jail and receiving very bad treatment : So many of them are being victimised. So many of them are facing repression all along the line. This is what is happening.

It is a good thing that my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta, moved it because if the Jana Sangha, which is in charge of the Delhi Administration, and the Central Government, which has the last say in this matter, sit down together and try in a co-ordinated manner to settle this question, certainly it could be done.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We are prepared to do it.

16 HRS.

SHRI H. N. MUKERJEE : I would like to ask the Education Minister to remember that he was himself a member of the Kothari Commission and what

[Shri H. N. Mukerjee]

the Kothari Commission has recommended is only in regard to the minimum salary. The Kothari Commission has also expressed a desire that more ought to be paid with reference to local conditions and also with reference to the scales of pay in comparable occupations under Government services in those States. Delhi teachers have special qualifications and have to deal with a very special kind of pupils and are living in a city which is very difficult on account of transport and the cost of living being so very high. I have no time to go into all those details. Delhi teachers do have to have more additional qualifications for getting jobs which are to be secured more easily elsewhere—I do not have the time to refer to the scales prevalent in Haryana and Himachal Pradesh; my hon. friend has already referred to that—and, therefore, there is no ground whatsoever for the Minister to come forward and say that Delhi teachers are getting more than what they should get.

They have been very patient; they have been very dignified and they are fighting today in a manner which should evoke the admiration of everybody. I wish the Education Minister to respond in his own spirit. He should pull his weight in the Cabinet and he should not behave like the Home Minister who has said that law and order should be of paramount consideration—that has been reported in the papers—in regard to teachers. The law and order matter should not be paramount here. He should have the quality of sympathy and imagination. That is his duty and that is his responsibility.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Member from that side said that there has been no strike in U.S.A. I submit respectfully that three or four years ago, there was a strike of all the teachers in New York. I do not know how many of them were there....

SHRI D. N. PATODIA: That is illegal.

SHRI D. C. SHARMA: In Ireland, the teachers went on strike and paraded the streets of Dublin for six months to have their salaries raised. I do not know from where my hon. friend has got the information.

Sir, I wish to submit very respectfully that the teachers' cause, as I understand it, is above party politics. It is not my cause; it is not Shri Kanwar Lal Gupta's cause. It is the nation's cause. Anyone who betrays the teachers is betraying the nation. He is not only trying to jeopardise the present generation of students but he is also trying to put to risk the future generation of students and he is trying to build up a citizenship based on fear, cowardice, incompetence and what not. Therefore, I say, the teachers' cause should be the paramount cause in this country.

I want to pay my humble tribute to the teachers of Delhi for conducting themselves in the most decent, in the most gentlemanly behaviour and in the most dignified manner. If anybody says that they have done wrong, I think, that man should be punished. The Director of Education should be dismissed straightway. It is he who is responsible for the harassment to the teachers.

I want to say that the hon. Education Minister has done his best but that best has not gone very far. I am afraid this type of agitation may spread to Punjab, Haryana and all over India. Therefore, I request him, as a former teacher, to call a meeting, a joint council, of teachers and discuss with them the problem.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत सी बातें जो शिक्षकों के बारे में कही गई हैं, मैं समझता हूं कि उन बातों को कह कर शिक्षकों के प्रति अन्याय किया गया है। यह ठीक नहीं है। उन्होंने स्ट्राइक की इसलिये हम उनको गालियां दें यह उचित नहीं है। यह कहा गया है कि उनको स्ट्राइक नहीं करनी चाहिये थी। यह मैं भी मानता हूं। लेकिन शिक्षकों के प्रति हकूमत की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को उसे भी निभाना चाहिये था। अपनी जिम्मेवारी को हकूमत निभाती नहीं है और उलटे

शिक्षकों को दोष दिया जाता है कि उन्होंने यह गलती की है। इस आधार पर उनको गाली दी जाए इसको मैं कबूल नहीं करूंगा।

सवाल यह है कि कोठारी कमिशन ने जो सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों को हम यहां लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि यहां के शिक्षकों को अगर स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर किया है किसी ने तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और कांग्रेस दोनों ने किया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : गलत है।

श्री एस० एम० जोशी : मैं आपको बता सकता हूं। जिन के हाथों में दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वे केन्द्र को यह कहते कि अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम नहीं चलायेंगे या स्कूल हम नहीं चला पायेंगे तो क्या आपका खयाल यह है कि मोरारजी भाई इसको मानने से मना करते? दोनों को साथ बैठना चाहिये था और मोरारजी भाई को मनवाना चाहिये था। फिर देखते कि कैसे नहीं मानते। जब उनकी उचित मांगों को माना नहीं जाता है तो शिक्षक क्या करें?

यहां पर अमरीका की बातें बताई जाती हैं। वहां का सब कुछ बताया जाता है। लेकिन कहां अमरीका और कहां भारत। लेकिन आप देखें कि अमरीका से प्रो० गैलब्रेथ यहां आए थे और जाते समय वह क्या कह गए हैं। जाती बार वह यह कह गए हैं कि हिन्दुस्तान के लोग अगर यह सीख लें कि आदमी के ऊपर ज्यादा खर्च हो बनिस्वत बिल्डिंग्ज़ वगैरह जो हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा।

आप देखें कि कोठारी कमिशन ने लिखा क्या है। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह कोई गैर जिम्मेदारी की भावना से नहीं लिखा है। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है :

"The future of education and consequently of the nation is at stake and the price must be paid. We believe that we can and should find the funds needed."

फंड्ज तो मिलने चाहियें। अब फंड्ज़ कहां से मिल सकते हैं इसका रास्ता मैं आपको बतलाता हूं। एक रचनात्मक सुझाव मैं देना चाहता हूं। जहां तक इस रिपोर्ट के दसवें चैप्टर का सम्बन्ध है, हकूमत का कहना यह है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिये हम उनको दे नहीं सकते हैं। मेरा सुझाव यह है कि शिक्षक और आप बैठ जायें और एक आर्बिट्रेटर आप मुकर्रर कर लें। वहां इसके ऊपर विचार हो कि हमारे पास क्या फंड्ज़ हैं। सब बातों को मद्देनजर वहां रखा जाए और पता लगाया जाए कि दिल्ली के शिक्षकों को हम ज्यादा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं और वहां पर इसका निर्णय कर लिया जाए। अगर आर्बिट्रेटर देने के लिए कह देता है तो हम लोगों को उसके निर्णय को मान लेना चाहिये। अगर सरकार नहीं देती है तो मैं कहूंगा कि मोरारजी देसाई साहब का सब लोगों को मिल कर घेराव करना चाहिये।

SHRI S. K. SAMBANDHAN (Tiruttani) : It has become most unfortunate in this country that the rights and demands, however much genuine they are and from whichever section of the population they come from, are to be recognised or conceded only after a strike. This is the situation that has been created by the ruling Party by ruling over the country for the past so many years. It is more unfortunate that teachers who are in a sacred profession and who are esteemed by every section of the people and who are people who mould the future generations are made to strike, and particularly at Delhi, the headquarters of the Central Government. It is for the Government and the people concerned to sit together across the table and solve the issues.

I understand that thousands of teachers have been suspended. It is most unfortunate that in place of the suspended teachers, some volunteers of some political parties are being trained

[Shri S. K. Sambandhan]

to handle the classes. Teaching is not an industry or any such thing. I can understand that for the purpose of defence for the immediate necessity some temporary recruits could be taken. But teaching is not such a profession. After all, the students can afford to wait for one week or even two weeks if necessary. So. I do not see why temporary recruitment should be made. It is for Government to come forward and see that the recruitment of volunteers of certain political parties to handle classes is stopped forthwith because that will lead to grave dangers. I warn this Government of that.

Once again. I want the Government and the people concerned to sit together and discuss the matter. For everything we have talks. We have peace talks...

AN HON. MEMBER: Even with the Naga hostiles.

SHRI S. K. SAMBANDHAN : For anything and everything we have talks across the table. I believe that the teachers' case can also be settled across the table if only Government and the other people concerned take proper steps.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Shri J. B. Kripalani. He may just put one question only.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : I would take only one minute. I do not understand why Government appoint committees or commissions without calculating the resources that they have at their disposal. I would request the Congressmen to put some wisdom in the brains of their Government that when they appoint a committee or a commission they are bound by their recommendations just as we are bound by the recommendations of the tribunal on Kutch. If they have no desire to carry them out, let them not appoint committees and commissions for any increased payments.

SHRI K. ANIRUDHAN (Chiryainkil) : I find from the discussion that has gone on here that the matter is settled almost. The members from the other side also appreciate the teachers' strike and they are keen to settle this issue.

SHRI TENNETI VISWANATHAN (Visakhapatanam) : The elections are coming.

SHRI K. ANIRUDHAN : The teachers have been divided into different sections. One section of teachers is controlled by the Delhi Administration. Another section is controlled by the Government of India, this, that and the other. A third section is controlled by the New Delhi Administration....

AN HON. MEMBER : None by the Government.

SHRI K. ANIRUDHAN : I do not think so.

Since these teachers are divided into three compartments and they are controlled by these three sections of administrators, there is no coordination between them. So. I feel, as someone has suggested, that if these three sets of people who are now at the helm of affairs sit together and discuss the matter, it can be easily settled.

Regarding the teachers' movement now, we find that the Government of India are adopting repressive measures. The hon. Minister of Education has himself come from the teachers' movement, and he should not have allowed this kind of repressive measures against the teachers ....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the hon. Member should conclude. Otherwise, the hon. Minister will not be able to reply. I have to adjourn the House at 4.30 p.m.

SHRI K. ANIRUDHAN : Now, the poor teachers who are on strike have become the victims of the two sets of people in power, the Jan Sangh people in the Delhi Administration and the Congress people at the Centre. It is because of this play of politics that the demands of teachers have become difficult to solve.

So it is better to settle this issue very soon without escalating it further.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : I understand the Minister's difficulties on the question of resources. But I would like to ask why, if he is not able to give actual cash, he has not made any attempt at all even to provide the teachers with amenities like housing, medical facilities and such other things. In factories, even unskilled labour of the lowest cadre is given these things. When they are giving a salary of Rs. 120 or 150, which you would not pay even to your lowest paid servant, what can Government, if it cannot provide actual cash relief, do to provide the teachers with other reliefs by way of amenities of the kind I have mentioned ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : उपाध्यक्ष जी, इतनी शीघ्रता से जैसे आप गाड़ी ले चलना चाहते हैं इस गंभीर समस्या पर गंभीरता के साथ कुछ कहना कठिन है। केवल दो प्रश्न आप के माध्यम से इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद देश को यह सौभाग्य मिला है जो शिक्षा मंत्रालय कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आया है जिन का शिक्षा के साथ कुछ संपर्क रहा है। पिछले संसद् के अधिवेशन में जब शिक्षकों की ओर से दिल्ली में इसी प्रकार की आवाज उठी थी, तब एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि अध्यापकों की समस्या पर मैं सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा। उस समय भी मैं ने यह कहा था कि सहानुभूति शब्द से अगर अध्यापकों का और उन के बच्चों का पेट भर जाता हो तो यह शब्द उन के लिए पर्याप्त रहेगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों के प्रतिनिधियों की और कुछ संसद् के सदस्यों की भी एक बैठक बुलायी। मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य समझिये कि उस में मैं भी उपस्थित था। उस में यह निश्चय किया गया कि शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और अध्यापकों के प्रतिनिधि दोनों मिल कर के बैठेंगे। अध्यापक सरकार की स्थिति को समझेंगे और सरकार अपनी स्थिति अध्यापकों को समझायेगी। उस के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

पहली बात तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब लिखित रूप में भी अध्यापक-संघ के मंत्री को यह कहा गया था और हमारी बैठक में भी यह बात कही तो फिर कौन-सी कठिनाई इस प्रकार की आ गई कि अध्यापकों के प्रतिनिधियों को निर्णय लेते समय विश्वास में नहीं लिया गया ?

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि आज बाजार में महंगाई सब के लिए एक समान है चाहे सरकार के दूसरे विभागों के कर्मचारी हों या अध्यापक हों। इसलिए महंगाई या वेतन उन को भी उसी अनुपात में मिलना चाहिए जिस अनुपात में सरकार के और दूसरे विभागों को दिया जाता है।

तीसरी बात जिस को कह कर मैं बैठता हूं वह यह कि सरकार अपना यह दुराग्रही रुख छोड़े। यह बात जो समाचार-पत्रों में आई है कि सरकार अध्यापकों से बात करने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री त्रिगुण सेन के होते हुए शिक्षा मंत्रालय से इस प्रकार की आवाज का आना न तो सरकार के लिए शोभा की बात है और न शिक्षा मंत्रालय के लिए ही शोभा की बात है। इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूं कि यह अध्यापक चाहे दिल्ली के हों या भारतवर्ष के हों अध्यापक, अध्यापक हैं और वह राष्ट्र के निर्माता हैं। वह चीन या पाकिस्तान से आये हुए नहीं हैं। इसलिए सरकार अपने दुराग्रही रुख को छोड़े। अध्यापकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर कोई समाधान निकाले जिस से जिन के हाथ में नई पीढ़ी के निर्माण का काम है वे सही ढंग से अपने काम को कर सकें और देश में इस प्रकार की विषम स्थिति पैदा न हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Sheo Narain. One question only. Then I will call the Minister.

SHRI A. S. SAIGAL: (Bilaspur): You must extend the time. This is not at all correct on your part. We are all concerned in this matter.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then I will have no alternative but to call the Minister straightway. Every Member is concerned. I know it.

SHRI A. S. SAIGAL: Even in my own State in the Chattisgarh division I my very much concerned with the plight of the teachers. So you must give us an opportunity to have our say.

श्री शिवनारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में चपरासियों की तनख्वाह 100 रुपये के करीब है, लेकिन इनकी बदइन्तज़ामी की वजह से, चूंकि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जनसंघ के हाथ में है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन टीचरों को आपने मौअत्तिल किया है, उनकी जगह पर किन को एप्वाइन्ट किया है, उन का सिलैक्शन ठीक किया है या नहीं? अगर वह 11 लाख रुपए का इन्तजाम नहीं कर सकते, तो आप दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को डिज़ाल्व क्यों नहीं कर देते?

SHRI M. L. SONDHI: May I know whether the Minister is prepared to refer Chapter III for arbitration, because this is the only basis on which the matter can be settled? (*Interruptions*) This is an occasion which calls for statesmanship, which calls for certain courageous effort. There is one footnote there. You are taking advantage of that footnote. (*Interruptions*) I shall speak, I shall not sit down. (*Interruptions*).

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: You do not want to listen to the Minister? I shall adjourn at 4.30.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): Will not my party get a chance?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Kabir also wanted to speak. There are several teachers. It is not a question of party.

SHRI SRINIBAS MISRA: I am sitting down under protest. This is very unfair. People who shout and are undisciplined are getting chances, and because we are quiet, you are bypassing us. In protest I walk out.

(*Shri Srinibas Misra then left the House*).

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN): I have listened with great interest to the discussion on the strike by the Delhi teachers which commenced on the 19th of this month and is continuing.

I have been touched by the expressions of sympathy of all the hon. members for the Delhi teachers.

AN HON. MEMBER: Lip sympathy.

DR. TRIGUNA SEN: I am touched by your lip sympathy? I do not know.

AN HON. MEMBER: Your party's lip sympathy. (*Interruptions*).

DR. TRIGUNA SEN: I have been in full sympathy with the lot of the teachers. In fact, it has always been my endeavour and that of my Ministry to improve as much as possible the working conditions of the teachers throughout the length and breadth of the country.

Shri Kanwar Lal Gupta has said that I made a misleading statement and that there was no change in 1959. I am told that the Second Pay Commission, while recommending the revision of pay scales of all categories of staff did not consider the pay scales of the teachers. Even then, the Ministry of Education and the Government of India agreed to implement the recommendations of the Commission for merger of the D.A. with the salary of the teachers as in the case of the employees of the Government.

He has stated that we have not implemented the Kothari Commission's recommendations *in toto*, but the Kothari

Commission did not recommend a total national salary scale or total amoluments.

Thirdly he says that according to the recommendations of the Delhi Administration it will cost only Rs. 38 lakhs, but the Government did not accept it.

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura) : Are not the salary scales of your cooks, servants and peons higher than those of the teachers ?

DR. TRIGUNA SEN : I am replying to the points raised by hon. Members. I had a discussion with Dr. Kothari himself. The revised scales of pay that had been announced by me do fulfil the recommendations of the Kothari Commission. Mr. Gupta said that the salary scale recommended by the Delhi Administration, if implemented, would cost about Rs. 38 lakhs. It is not correct. I want to say it will cost Rs. 91 lakhs.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Recurring ?

DR. TRIGUNA SEN : Salary scales, as I understand them, are always recurring expenditure. It cannot be capital expenditure. Shri Randhir Singh wanted that the recommendations of the Education Commission should be implemented. We have done so. Mr. Patodia says that we should not make it a prestige issue. I can assure hon. Members that I do not stand on any false notion of prestige. I started my life as a teacher on Rs. 60 and I know the difficulties of a teacher. I am not ashamed to say that when I was teacher at the end of the day I had to satisfy myself with one or two bananas. That apart, I do not stand on any prestige. Mr. Shashi Bhushan suggested that the teachers were arrested, suspended and dismissed. I can assure the hon. Members here that there is no hand of the Government in the arrest, and suspension of the teachers. I maintain it is an untenable situation...

AN HON. MEMBER : Who did it ?

DR. TRIGUNA SEN : Ask yourself. Prof. Mukerjee maintained that the Kothari Commission has recommended a national minimum and that we should take into account the local conditions. I agree there are difficulties of housing, transport, etc. in Delhi. But I do not agree that the teachers in Delhi are to teach a special class of students as mentioned by Prof. Mukerjee. Children are the same throughout the country. The implication of his statement is that not enough has been given considering the difficulties of the teachers here. The tabular statement gives the emoluments recommended by the Education Commission, and the emoluments now fixed as their revised scales. ...(*Interruptions*). Prof. Sharma said that we should be prepared to discuss with teachers and Shri Shastri also said so. As mentioned by both of them, when we discussed with the teachers, they were in fact present. We had met the teachers for about four ours and I am always ready to meet the teachers. I am meeting them actually every day...(An Hon. Member: What about arbitration ?) It is not correct to say that I refuse to meet them. Mr. Anirudhan referred to the repressive measures. I can assure him, as I said before, that these measures of suspension and other things are not done by the Government. But I agree with the Home Minister when he says that whether a person is a teacher or a student or a Member of Parliament or even a Minister, he should be treated as any other common citizen if he breaks the law.

Shrimati Sharda Mukerjee suggested about other facilities and amenities and asked why we did not consider them. As I said in the beginning when I joined as a Minister, it is my duty to see that the recommendations of the Education Commission are implemented. After having revised the pay scales we are now at it, and I would welcome suggestions from Shrimati Sharda Mukerjee, when we are considering how best we can give them the health services, housing accommodation and facilities to improve the academic qualifications and the measures to improve the working conditions and the efficiency of teachers.

Sir, I have been pleading with all the State Governments to implement the recommendations of the Education

[Dr. Triguna Sen]

Commission. I find Members coming from all the States are also pressing that those recommendations must be implemented. May I take this opportunity to request my hon. friends that when they go home they should plead with their respective State Governments to see that the recommendations are implemented. (*Interruption*).

An HON. MEMBER : What about arbitration ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. I will have to adjourn the House. Let him conclude.

DR. TRIGUNA SEN : Coming back to the present strike, there are two aspects of the present Delhi strike to which I must draw the attention of the House. (*Interruption*). There is an impression that forgetting every demand met, right or wrong, the agitational approach is the only approach that pays.

AN HON. MEMBER : Why not arbitration ? (*Interruption*)

DR. TRIGUNA SEN : This is a lamentable impression which any responsible Government which believes in democracy and parliamentary practice must discourage. (*Interruption*) In the present case, the teachers have adopted an agitational approach. They have also chosen to strike at a time when the annual examinations are so close. I am pained to say that in taking this decision the teachers have shown scant regard to the interests of the younger generation.

SOME HON. MEMBERS : No, no.

DR. TRIGUNA SEN : No responsible parents can ever be expected to sacrifice the best interests of their children. Similarly, no teacher worth the name can ever be excused for such total neglect of the educational interests of the young children entrusted to his care. I do hope that the teachers will appreciate the gravity of the situation and reconsider their decision to continue the strike.

16.33 HRS.

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*].

RE : POINT OF ORDER

SHRI NATH PAI (Rajpur) : Sir, I rise on a point of order.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

MR. SPEAKER : One at a time. Mr. Nath Pai.

SHRI NATH PAI : May I draw your attention, Sir ? I am told today is the birthday of the Deputy Prime Minister and I wish him well.

MR. SPEAKER : That is not a point of order.

SHRI NATH PAI : May I draw your attention to rule 25 and to the proviso to that rule ? Under this proviso, I claim your protection for the redressal of a grievance which the whole opposition has been labouring under since yesterday—I stand corrected; the whole opposition minus Mr. Masani, those who think that the injustice has to be removed.

Sir, I want to appeal to you under this proviso which says,

> "...the Speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variation."

I am going to plead with you for the variation of the business set down today. I concede that under the notification of the President, today has been set for the presentation of the estimates for this year by the Deputy Prime Minister. We have seen it and it has appeared in the bulletin. I am asking your protection for taking up the unfinished business which